[Shri P. Rajagopal Naidu]

This year, the rains failed and the agriculturists are not able to sow the ground nut even. If rains do not come within a month, even the standing crops will fail. At present, the agricultural labourers are not able to get work and their condition is becoming precarious.

Only old schemes under Food for Work scheme are being continued and new works are not taken up, due to paucity of foodgrains sent by the Central Government. Unless the Quota of foodgrains under special Plan is increased with specific instructions to the A.P. state Government to spend them is Rayalaseema for taking up new works, it will be very difficult to protect the agricultural workers in that area.

(ii) NEED FOR NATIONALISATION OF KUMARDUVI. ENGINEERING WORKS, DHANBAD.

SHRI A. K. ROY (Dhanbad). We are shocked to know that the Kumarduvi Engineering Works, One of the leading engineering units of the country, employing some 4000 workmen, is being handed over to a monopoly house, TISCO. This concern was previously owned by Bird & Co. and later it was transferred to Helgers Group Company.

The factory was lying closed since July 1979 due to the mismanagement and draining of its working capital with the result, the old company had to undrgo liquidation and the factory was placed under the receivership of Allahabad Bank by the order of the Calcutta High Court.

At the time of closure the Kumarduvi Enneering Works was indebted to Allahabad bank about Rs. 8/-crores. State Bank of Bihar about Rs. 2/-crores and the workmen in the form of Provident Fund, earned wages etc, Some Rs. 14 lakhs.

Since July 1979, the workmen are in peaceful satyagraha demanding nationalisation of the company and reopenin it. Serval discusssions were held between the Allahabad Bank Government of Bihar and the Central Government in this connection.

The matter was raised in the Parliament on March 26, in the form of Unstarred Question No. 1699 and then again in the form of Calling Attention Notice and on both the occasions the Minister of Industry assured the House to reopen the factory within the shortest possible time under some public sector management.

In this case several alternatives were also open to the Government. It could reopen the factory under its direct management as the case of Swadeshi Cotton Mill of Kanpur during the Janata Government or the factory could be placed under the mangement of Coal India Limited or TISCO, Already operating in the area. But to our great dismay we have come to know that this important Engineering concern is being handed over to the TISCO already a formidable monopoly House even circumventing the provision of MRTP Act and in contravention of the professed economic policy followed so far. So this handing over of the Kumarduvi Engineering Works from its present possenssion of Allahabad Bank to the TISCO not only constitutes a breach of commitment to the House but also a betrayal of the policy of the Government apart from disappointing the workers so long agitating for the take over of the Company by the Government.

(iii) REPORTED TENSE SITUATION IN FARIDABAD DUE TO DISCONTENTMENT AMONG INDUSTRIAL WORKERS.

श्री राम विलास पासवान : (हाजीपुर) : फरीदाबाद में मजदूर असंतोष के कारण स्थिति बड़ी तानवपूर्ण है । लगभग 10,000 मजदूर फरीदावाद में ट्रेडयूनियन में सक्रिय रूप से भाग लेने के कारण विभिन्न उद्योगों से निकाल दिये गये हैं और वे फरीदाबाद मे रोजगार पाने के लिए मारे-मारे फिर रहे है । ईस्ट इण्डिया काटन मिल, जिसके लगभग 3200 मजदूर पिछले वर्ष 23 जुलाई 79 को फैक्टरी से बाहर निकाल दिये गये थे, क्योंकि उन्होंने एक माग-पत्र दिया था, उस के कारण 17 अक्तूबर 79 को फरीदाबाद बन्द हुआ था और एक भयानक गोलीकाड हो गया था जिसमें दर्जनों मजदूर मारे गये थे और सैकड़ों घायल हुए थे । इसके बाद हरियाणा सरकार के प्रतिनिधि के साथ स्थानीय ट्रेड यूनियन नेताओं के साथ एक समझौता 19-11-79 को हुआ था जिसमें मृतक मजदूरों के परिवारों को 10,000 (दस हजार रुपये) देने तथा विवादास्पद उद्योगो के मजदूरों और मेनजमेंन्ट में समझौता कराने तथा 1,000 झुग्गी-झोंपड़ियों में रहने वाले मजदूरों को मकान बना कर देने का समझौता किया गया था, लेकिन अभी तक सरकार ने समझौते को लागू नही किया । मैंने खुद फरीदाबाद जा कर स्थिति का अध्ययन किया है । हरियाणा पुलिस उद्योगपतियों का साथ दे कर मजदूरों पर दमन करती है । आंतक का वातावरण बनाने के लिए सारे फरीदाबाद में बटालियन हरियाणा शस्त्र पुलिस तथा दो बटालियन सी० आर० पी० स्थायी तौर पर बुला ली गई है । मजदूरों को पुलिस द्वारा गलत और झूठे मुकदमे लगा कर इधर-उधर के केसों में फंसाया जा रहा है । फैक्टरी द्वारा पुलिस और गुण्डों के बल पर मजदूरों पर जुल्म ढाया जा रहा है ।

मैं सरकार से अपील करता हूं कि यदि वह फरीदाबाद की विस्फोटक तथा तनावपूर्ण स्थिति को शान्त करना चाहती है, तो केन्द्र सरकार तुरन्त हस्तक्षेप करे और :--

1 निकाले गए मजदूरों को काम पर वापस लिया जाए ।

2 पुलिस दमन बन्द किया जाए और पुलिस द्वारा मजदूरों और उनके नेताओं पर झूठे मुकदमे वापिस लिए जाएं ।

3 17 अक्तूबर 1979 कांड के शहीद मजदूरों के परिवारों को सरकार द्वारा तय समझौते के तहत दस हजार रुपये मुआवजा दिया जाए ।

4 17 अक्तूबर 1979 कांड की न्यायिक जांच कराई जाए ।

5 उक्त कांड के मजदूरों एवं मजदूर नेताओं पर चलाए जा रहे झूठे मुकदमे वापिस लिए जाएं ।

(iv) REPORTED SHORTAGE OF EXERCISE BOOKS AND TEXT-BOOKS IN UTTAR PRADESH.

श्री बी० डी० सिंह (फूलपुर) : उत्तर प्रदेश में इस वर्ष अभ्यास पुस्तिकाओं एवं पाठ्य पुस्तकों का अभूतपूर्व अभाव पैदा हो गया है । प्रदेश के बाजारों में नियंत्रित मूल्य की पुस्तिकायें खोजने पर भी नहीं मिलेंगी । प्रदेश के शिक्षा मंत्री ने जून में ही यह आशंका व्यक्त की थी कि पुस्तिकाओं का अभाव होने की सम्भावना है । उन्होंने नियंत्रित कागज के कोटे में वृद्धि की मांग केन्द्रीय सरकार से की थी तथा नियंत्रित कागज की पूर्ति भी तत्काल करने का आग्रह किया था । सरकार द्वारा समय पर ध्यान न देने से यह स्थिति और गम्भीर हो गई । इस संकट के लिए केन्द्रीय एवं प्रान्तीय दोनों सरकारें उत्तरदायी हैं । यह सर्वविदित है कि जुलाई से शिक्षा सत्र प्रारम्भ होता है और उसी समय सभी विद्यार्थी उत्तर पुस्तिकाओं एवं पाठ्य पुस्तकों का क्रय करते हैं । फिर पुस्तिकाओं की आपूर्ति में इस प्रकार की अनुत्तरदायित्व पूर्ण शिथिलिता क्यों हुई ? नियंत्रित कागज की पुस्तिकाओं के अभाव में अनियंत्रित कागज से बनी पुस्तिकाओं, जिन का निर्माण बड़ी तेजी से हो रहा है का विक्रय करके व्यापारी निर्धन छात्रों एवं अभिभावकों का गहन शोषण कर रहे हैं । माननीय शिक्षा मंत्री कृपया इस बात को स्पष्ट करें कि केन्द्रीय सरकार द्वारा विभिन्न प्रान्तों को कागज का कोटा किन-किन आधारों पर निश्चित किया जाता है ? उत्तर प्रदेश के क्षेत्र एवं उसकी जनसंख्या को ध्यान में रखते हुए उसके साथ न्याय क्यों नहीं किया गया ?

अनियंत्रित कागज द्वारा तैयार की गई पुस्तिकाओं का एक ओर तो निर्माताओं ने आकार (लम्बाई एवं चौड़ाई दोनों) को बहुत छोटा कर दिया है और दूसरी ओर उनके मूल्य में अप्रत्याशित वृद्धि कर दी है । गत वर्ष नियंत्रित कागज से बनी हुई पुस्तिकायें सर्वत्र उपलब्ध थीं । 64 पृष्ठ की अभ्यास पुस्तिका तीस पैसे में प्रत्येक विक्रेता के यहां मिल जाती थी । इस वर्ष उन पुस्तिकाओं के अभाव में 80 पृष्ठ वाली अनियंत्रित पुस्तिका जिस का आकार नियंत्रित पुस्तिका से काफी छोटा है, बाजार में एक रुपये में बिक रही है इसी प्रकार पाठ्य पुस्तकों का भी अभाव उत्पन्न हो गया है । पुस्तकों के मूल्य में डेढ़ से ले कर अढ़ाई गुना तक की वृद्धि देखने में आई है । सरकार का ध्यान इस ओर भी जाना चाहिये कि जिन पुस्तकों का मुद्रण गत वर्ष या इसके पूर्व हो गया था, वे पुस्तकें भी इस वर्ष बढ़े हुए मूल्य छाप कर बेची जा रही हैं ।

उत्तर प्रदेश में नियंत्रित पुस्तिकाओं का वितरण सरकार सहकारी संघों द्वारा कराने जा रही है, जिन पर से जन साधारण का विश्वास उठ चुका है । वितरण प्रणाली भयंकर दोषों से ग्रस्त है । नगरों के विभिन्न क्षेत्रों एवं सुदूर गांवों के विद्यार्थियों को ये पुस्तिकायें किस प्रकार उपलब्ध हो सकेंगी, सम्भवतः सरकार ने इस पर चिन्तन करने का कष्ट नहीं उठाया है । भयंकर आर्थिक तनाव में जी रहे अभिभावकों एवं छात्रों का यह शोषण सरकार की शिक्षा के प्रति उपेक्षा, कच्छप गति एवं कल्पना शून्यता का परिणाम है । माननीय शिक्षा मंत्री इस सम्बन्ध में कृपया एक वक्तव्य दें और यह आश्वासन दें कि रुचित मूल्य की शिक्षा सामग्रियों के अभाव में छात्रों एवं अभिभावकों का और अधिक शोषण नहीं होगा ।

(v) NEED FOR RUNNING ADDITIONAL TRAINS BETWEEN BANKURA AND RAINA ON BANKURA DAMODAR RAILWAY LINE.

SHRI AJIT KUMAR SAHA (Vishnupur) : Earlier, three pairs of trains were running in the Bankura-Damodar Railway line between Bankura and Raina. But at present only towo pairs of trains are being run causing great hardship to a large number of peole of the area, particularly the agricultural labourers and the tribal people who move in large numbers during sowing and harvesting season. There is no other means of communication for these people and others. The divisional superintendne of Adra division, South Eastern Railway had promised to run trains in the above railway line by diesel engines, which unfortunately has not yet been implemented, nor the line is being properly maintained. Even routine maintenance work has not been done for a long time.

I, therefore, would like to request the Railway Minister to look into the matter and see that atleast three pairs of trains are run for the convenience of the poor agricultural labour and others.

———